भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1346

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप्स

1346. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;
(ख) देश में ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) द्वारा वास्तव में मौजूद नए स्टार्ट-अप्स और दुकानों को किस प्रकार सहायता और बढ़ावा दिया जाएगा;
(ग) क्या सरकार ने इस इकोसिस्टम के हितधारकों से सुझाव मांगे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या ओएनडीसी प्लेटफार्म शुरू करने से पहले उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127(अ) के तहत निर्धारित पात्राता शर्तों के अनुसार कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान करता है। 30 नवंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा देशभर में 84,012 कंपनियों को मान्यता प्रदान की गई है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान डीपीआईआईटी से स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त् कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त् कंपनियों की संख्या
2019	11,328
2020	14,534
2021	20,089

(ख) से (च): स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स मूल्य श्रृंखला के किसी भाग के लिए अभिनव और विशिष्ट समाधान का विकास करके डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) में भाग ले सकते हैं, भारत में ई-कॉमर्स के व्यापक इकोसिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं तथा जल्द विकास कर

सकते हैं। दुकानदार ई-कॉमर्स पर खुद को दर्शा सकते हैं तथा ओएनडीसी पर अपनी पसंद के विक्रेता नेटवर्क भागीदार के जरिए अपनी शर्तों पर कारोबार कर सकते हैं।

ओएनडीसी ने सार्वजनिक तौर पर विचार-विमर्श के लिए जनवरी, 2022 में कार्यनीति पत्र में अपने समग्र दृष्टिकोण को प्रकाशित किया तथा 29 सितंबर, 2022 को नेटवर्क में विश्वास बढ़ाने के अपने दृष्टकोण को प्रकाशित किया है। नेटवर्क भागीदारों तथा विस्तृत इकोसिस्टम से प्राप्त सुझावों को ओएनडीसी नीतियों, कोडबेस के साथ-साथ नेटवर्क के समग्र विकास में शामिल किया गया है।

*****